fortified bread using lysine in their products ; and

(d) whether lysine is manufactured in India or it is imported ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM). (a) The Company is marketing fortified bread under the trade name "Modern Bread". It is not correct to say that this is advertised as "milk bread".

(b) Lysine and milk powder are added at 0.1% and 0.55% respectively of the volume of wheat flour.

(c) No.

(d) Lysine is at present not manufactured commercially in India and is imported.

Shifting of Sub-Post Office from Kadwad Village (Mysore State)

8488. SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people from Kadwad Village, District Karwar, Mysore State have protested against shifting of the Sub-Post Office from that place ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes.

(b) The matter was considered, but as the present Post Office building is not sufficiently spacious, not well-ventilated and not easily accesible during the rainy season, the shifting has been approved.

दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

8489. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन प्रयोक्ताओं पर टेलीफोन बिलों की काफी बड़ी राशि जमा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में क्रमशः कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) नवम्बर, 1967 से अब तक सरकार ने कितनी बकाया राशि वसूली की है और उन पर अभी कितनी राशि बकाया है ;

(घ) नवम्बर, 1967 से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) गत पांच महीनों में बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण कितने टेलीफोन कनेक्शन काटे गये ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 30 सितम्बर, 1967 तक जारी किए गये बिलों के लिए 1 जनवरी, 1968 को बकाया राशि 2.25 करोड़ रुपये थी ।

(ख) बकाया राशि में से 0.29 करोड़ रुपये की राशि 1965-66 की थी और 0.39 करोड़ रुपये 1966-67 के थे । 1967-68 (केवल सितम्बर 1967 तक) की बकाया राशि 0.49 करोड़ रुपये थी । बाकी (1.08 करोड़ रुपये) की राशि 1965-66 से पहले की अवधि की है ।

(ग) नवम्बर-दिसम्बर 1967 के दौरान 1.55 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जा चुकी थी और जैसा कि पहले बताया गया है अभी 2.25 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की जानी है ।

(घ) वसूली करने के लिये स्मरणपत्र जारी करने, टेलीफोन काटने, प्रयोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां-कहीं आवश्यक हो अन्त में टेलीफोन काटने जैसे कदम उठाये जाते हैं ।

(ङ) लगभग 2,575 टेलीफोन कनेक्शन काटे गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास के लिये योजनायें

8490. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1 जनवरी, 1967 से अब तक केन्द्रीय

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कौन-कौन सी योजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य योजनाओं के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं स्थगित की तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रहीं हैं तथा उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष पदों को छोड़ कर राज्यों में कृषि विकास के लिए योजनाओं को सीधा कार्यान्वित नहीं करती है। वह कृषि विकास कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिए राज्य सरकारों को केवल वित्तीय सहायता देती है। फिर भी, कुछ योजनायें ऐसी हैं जो कृषि कार्यक्रमों के कुछ पक्षों से सम्बन्ध हैं जैसे मौलिक अनुसन्धान, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण तथा जांच मार्गदर्शी अध्ययन, विशेष सेवायें तथा कुछ अन्य, जो यद्यपि राज्यों में चालू हैं, तथापि केन्द्रीय सरकार के सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व में आती हैं।

(ख) से (घ). जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास

8491. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1957 से अब तक प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को कृषि विकास के लिये कितनी राशि की सहायता दी है ;

(ख) यह सहायता किन-किन योजनाओं की क्रियान्वित के लिए दी गई थी ; और

(ग) विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में किन-किन योजनाओं के लिए सहायता दी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्य योजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिये सहायता दी जाती है। वर्तमान विधि के अन्तर्गत, राज्य प्लान योजनाओं के लिये ऐसी सहायता राज्यों को विकास के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत निर्मुक्त की जाती है और वह किसी विशिष्ट योजना या योजनाओं के वर्ग के लिए नहीं दी जाती है। केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को विकास के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत 1956-57 से आज तक दी गई सहायता का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—1036/68]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई सहायता के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सहायता किसी राज्य के किसी भाग के लिये निर्दिष्ट नहीं की जाती है जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जब तक कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई विशिष्ट योजना किसी विशेष जिले व क्षेत्र में स्थितः न हो।

Sale of Fertilizers outside Priority Areas

8492. SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI MEETHA LAL MEENA :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have decided to liberalise the sale of fertilizers outside the priority areas ; and

(b) if so, how the prices of fertilizers are likely to be affected as a result thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Yes, Sir.